कुछ स्मारक डाक टिकट यदि स्टाक में बच जाती हैं, तो बाद में नियत डाक टिकटों के साथ, बेची जा सकती हैं। लेकिन आमतौर पर वह एक निश्चित अवधि के बाद उपलब्ध नहीं होतीं। नियत डाक टिकट, विशेष नियत डाक टिकटों सहित लगातार छापी जाती रहती हैं और सभी डाकघरों को उनकी मांग के अनुसार सप्लाई की जाती है।

(ङ) फिलहाल डा. अम्बेडकर पर सामान्य (नियत) डाक टिकट जारी करने का कोई प्रस्ताव नहीं है।

कश्मीर की स्थिति में सुधार किया जाना

1430. **श्री अनन्तराम जायसवाल :** क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने कश्मीर की स्थिति में सुधार लाने के लिए वहां के कतिपय नेताओं से, राजनीतिक और आर्थिक योजनाओं के बारे में विचार-विमर्श किया है; यदि हां, तो मुख्यतः किन-किन बातों पर विचार-विमर्श किया गया है;

(ख) उपर्युक्त योजना को कार्यान्वित न किये जाने के क्या कारण हैं; और

(ग) क्या सरकार उपर्युक्त योजना के कार्यान्वयन हेतु कोई समय सीमा निर्धारित करेगी ?

संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री और गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एम० एम० जैकब) : (क) से (ग) जम्मू और कश्मीर की स्थिति पर कश्मीर और उससे बाहर के नेताओं के साथ विचार-विमर्श किया गया और यह एक निरन्तर चलने वाली प्रक्रिया है। इसी बीच सरकार ने, विकास कार्यक्रमों में लोगों की भागीदारी और जिला प्रशासन के अन्य पहलुओं में लोगों की भागीदारी को प्रोत्साहित करने के लिए परामर्शदात्री ग्रुपों का गठन किया है। इस संबंध में दिशा निर्देश पहले ही जारी कर दिए गए हैं।

किलोमीटर स्कीम के अधीन निजी बसों के चलाये जाने से दिल्ली परिवहन निगम को हुआ घाटा

1431. **श्री अनन्तराम जायसवाल :** क्या जल-थल परिवहन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि दिल्ली परिवहन निगम को किलोमीटर स्कीम के अधीन निजी बसों को चलाये जाने के कारण घाटा उठाना पड़ा है;

(ख) यदि हां, तो पिछले तीन वित्तीय वर्षों के दौरान, वर्षवार, उक्त स्कीम के अधीन दिल्ली परिवहन निगम को हुए घाटे का ब्यौरा क्या है, और इसके क्या कारण हैं;

(ग) उन मदों का ब्यौरा क्या है जिनके अधीन दिल्ली परिवहन निगम को पिछले तीन वित्तीय वर्षों के दौरान घाटा उठाना पड़ा है और वित्तीय वर्ष 1990-91 के अन्त में इस तरह का कुल कितना घाटा हुआ है;

(घ) क्या भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक ने इस विषय पर इस प्रतिवेदन में प्रतिकूल टिप्पणियां की हैं; और

(ङ) यदि हां, तो उस पर सरकार की प्रतिक्रिया सहित उसका सार क्या है ?

जल-थल परिवहन मंत्रालय के राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) (श्री जगदीश टाइटलर) : (क) जी, हां।

(ख) से (ङ) दिल्ली परिवहन निगम के अंतर्गत निजी बसों के प्रचालन की किलोमीटर स्कीम को मार्च, 1988 से बंद कर दिया गया है। इस स्कीम के बंद होने से पूर्व के तीन वर्षों के दौरान किलोमीटर स्कीम के कारण निगम को

हुए घाटे का ब्यौरा इस प्रकार है :—

वर्ष	घाटा
	(लाख रु०)
1985–86	1635
1986–87	734
1987–88	596

घाटे का वर्ग वार ब्यौरा इस प्रकार है : (i) दि. प. नि. के पास-धारकों के लिए निजी प्रचालकों को मुआवजे का भुगतान, (ii) किलोमीटर स्कीम के अंतर्गत बसों के निजी प्रचालन के लिए लगाए गए अतिरिक्त कर्मचारियों को वेतन एवं भत्ते, और (iii) सड़क पर बसों के निजी प्रचालकों द्वारा प्रतिस्पर्द्धात्मक विपणन के कारण राजस्व की हानि ।

भारत के नियंत्रक एवं महालेखा-परीक्षक की रिपोर्ट में उल्लिखित कमियों को सुव्यवस्थित ढंग से दूर करने हेतु तथा ऐसी कमियों की पुनरावृत्ति को रोकने के लिए दि. प. नि. को निर्देश दे दिए गए हैं ।

Survey to limit the local Call per three minutes by MTNL, Bombay

1432. SHRI PRAMOD MAHAJAN: Will the Minister of COMMUNICATIONS be pleased to state.

(a) whether it is a fact that a recent survey by MTNL, Bombay has proved that most of the conversations are less than three minutes; and

(b) if so, whether Government still proposes to limit the local call per three minutes?

THE MINISTER OF STATE (IN DEPENDENT CHARGE) OF THE MINISTRY OF COMMUNICATIONS SHRI RAJESH PILOT): (a) Sir, recent study made by MTNL, Bombay on a limited basis showed that about 70 per cent of the local calls are less than 3 minutes duration.

(b) The proposal to limit local calls to three minutes is still under consideration of the Government and no final decision has been taken so far.

उत्तर प्रदेश में राष्ट्रीय राजमार्गों की स्थिति में सुधार, उनका रख-रखाव और सौन्दर्यीकरण

1433. **डा० रत्नाकर पाण्डेय :** क्या जल-भूतल परिवहन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उत्तर प्रदेश में राष्ट्रीय राजमार्गों की स्थिति में सुधार करने, उनके रख-रखाव और सौन्दर्यीकरण के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाये जा रहे हैं; और

(ख) वर्ष 1991–92 के दौरान इस शीर्ष पर कितनी राशि खर्च किये जाने की संभावना है ?

जल-भूतल परिवहन मंत्रालय के राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) (श्री जगदीश टाइटलर) : (क) राष्ट्रीय राजमार्गों के विकास के लिए सुधार और सुन्दरता संबंधी कार्यों को एक नियोजित तरीके से किया जाता है और यह निधियों की उपलब्धता पर निर्भर करता है । राष्ट्रीय राजमार्गों का विकास एक सतत् प्रक्रिया है जिसे उपलब्ध धनराशि के अनुसार प्रतिवर्ष किया जाता है ।

(ख) उत्तर प्रदेश में राष्ट्रीय राजमार्गों के विकास के लिए वर्ष 1991–92 के बजट में 60.00 करोड़ रु० का एक प्रावधान है । वर्ष 1991–92 के कुल परिव्यय में से इस समय उत्तर प्रदेश में राष्ट्रीय राजमार्गों के रख-रखाव के लिए 13.59 करोड़ रु. की राशि आवंटित की गई है ।